भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2913 का उत्तर

जौनपुर जिले में लेवल क्रॉसिंग

2913. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जौनपुर जिले में कुल कितने लेवल क्रॉसिंग हैं जहाँ सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) या रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को देश भर के प्रमुख शहरों और वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ने के लिए शुरू की गई या शुरू किए जाने वाले किसी भी नए एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्तमान में प्रगति पर या योजनाधीन नई लाइन सर्वेक्षण और परियोजनाओं की संख्या, उनकी कुल लंबाई, अनुमानित लागत सहित कितनी है;

(घ) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में नई लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशन उन्नयन और ओवरब्रिज सहित सभी रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में अपनी मूल निर्धारित पूर्णता तिथि से आगे लंबित हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): जौनपुर जिले में 409 करोड़ रुपए की लागत से समपारों के स्थान पर 14 उपरि/निचले सड़क पुल संबंधी कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो नियोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	स्थान	ऊपरी/निचले सड़क पुल/ पैदल पार पुल	लागत (करोड़ रू. में)	टिप्पणियां
1	जलालगंज के निकट समपार संख्या 30	ऊपरी सड़क पुल	37	यह कार्य द्वि-निकाय आधार पर निष्पादित किया जा रहा है, अर्थात रेलवे का भाग रेलवे द्वारा और पहुंच मार्ग का कार्य राज्य की एजेंसी द्वारा। ठेका प्रदान कर दिया गया है।
2	जौनपुर-जाफराबाद खंड पर समपार संख्या 42ए	ऊपरी सड़क पुल	37	यह कार्य द्वि-निकाय आधार पर निष्पादित किया जा रहा है, अर्थात रेलवे का भाग रेलवे द्वारा और पहुंच मार्ग का कार्य राज्य की एजेंसी द्वारा। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
3	बादशाहपुर के निकट समपार संख्या 64-बी	ऊपरी सड़क पुल	37	यह कार्य द्वि-निकाय आधार पर निष्पादित किया जा रहा है, अर्थात रेलवे का भाग रेलवे द्वारा और पहुंच मार्ग का कार्य राज्य की एजेंसी द्वारा। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
4	जौनपुर-जाफराबाद खंड पर समपार संख्या 43	ऊपरी सड़क पुल	38	यह कार्य द्वि-निकाय आधार पर निष्पादित किया जा रहा है, अर्थात रेलवे का भाग रेलवे द्वारा और पहुंच मार्ग का कार्य राज्य की एजेंसी द्वारा। सामान्य व्यवस्था आरेख को मंजूरी दे दी गई है।
5	समपार संख्या 23/सी श्रीकृष्ण नगर	ऊपरी सड़क पुल	46	यह कार्य द्वि-निकाय आधार पर निष्पादित किया जा रहा है, अर्थात रेलवे का भाग रेलवे द्वारा और पहुंच मार्ग का कार्य राज्य की एजेंसी द्वारा। सामान्य व्यवस्था आरेख को मंजूरी दे दी गई है। ठेका प्रदान कर दिया गया है। भू-तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है।
6	जौनपुर सिटी में समपार संख्या 9	ऊपरी सड़क पुल	70	ठेका प्रदान किया गया है।
7	जौनपुर-जाफराबाद पर समपार संख्या 38ए	ऊपरी सड़क पुल	68	सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
8	जाफराबाद-अयोध्या खंड पर समपार संख्या 57ए	निचला सड़क पुल	6	सामान्य व्यवस्था आरेख को मंजूरी दे दी गई है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत किया गया है।

9	जाफराबाद-अयोध्या खंड पर समपार संख्या 44/सी	निचला सड़क पुल	6	सामान्य व्यवस्था आरेख को मंजूरी दे दी गई है। विस्तृत अनुमान को स्वीकृत किया गया है।
10	जाफराबाद-अयोध्या खंड पर समपार संख्या 61	निचला सड़क पुल	6	सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
11	पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-प्रतापगढ़ जंक्शन-लखनऊ पर समपार संख्या 51	ऊपरी सड़क पुल	40.00	यह समपार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस कार्य को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल निकाय आधार पर शुरू किया गया है।
12	औंड़िहार जंक्शन-जौनपुर जंक्शन पर समपार संख्या 11	निचला सड़क पुल	6	सामान्य व्यवस्था आरेख को मंजूरी दे दी गई है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। ठेका प्रदान कर दिया गया है। बॉक्स की ढलाई कर दी गई है।
13	औंड़िहार जंक्शन-जौनपुर जंक्शन पर समपार संख्या 24	निचला सड़क पुल	6	सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
14	औंड़िहार जंक्शन-जौनपुर जंक्शन पर समपार संख्या 40	निचला सड़क पुल	6	सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति देना सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेल परिचालन में संरक्षा व रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता तय की जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (जून 2025) की अवधि के दौरान, भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या इस प्रकार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या
2004-14	4,148
2014-25 (जून 2025)	13,426 (उत्तर प्रदेश राज्य में 1649 पुलों सहित)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,00,860 करोड़ रुपए की लागत से 4,402 ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में 14,022 करोड़ रुपए की लागत से 736 ऊपरी/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

विद्युतीकरण:

भारतीय रेल में मिशन मोड पर रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है। अब तक, लगभग 99% बड़ी लाइन (बीजी) नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

अवधि	मार्ग किलोमीटर
2004 से पहले (लगभग 60 वर्ष)	21,801
2014-25	46,900

उत्तर प्रदेश राज्य में, जौनपुर जिले सहित पूरे मौजूदा बड़ी लाइन रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया गया है। सभी नई लाइन/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं का विद्युतीकरण करने के साथ स्वीकृत और निर्मित किया जा रहा है।

नई लाइन/दोहरीकरण/आमान परिवर्तन परियोजनाएँ:

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पूर्वांचल क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 6271 किलोमीटर लंबाई के 111 सर्वेक्षण (33 नई लाइन, 76 दोहरीकरण और 2 आमान परिवर्तन) स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पूर्वांचल क्षेत्र और जौनपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 49 रेल परियोजनाएँ (10 नई लाइन, 02 आमान

परिवर्तन और 37 दोहरीकरण), कुल 3,808 किलोमीटर लंबाई, जिसकी लागत 62,360 करोड़ रूपए है, स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 1,323 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2025 तक, 30,611 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है।

कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	10	1227	340	10517
आमान परिवर्तन	2	67	0	281
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	37	2513	983	19813
कुल	49	3808	1323	30611

पूर्वांचल क्षेत्र और जौनपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रूपए/वर्ष
2025-26	19,858 करोड़ रूपए (लगभग 18 गुना)

पूर्वांचल और जौनपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली, हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	आगरा-इटावा नई लाइन (110 कि.मी.)	427
2	गुना-इटावा नई लाइन (348 कि.मी.)	683
3	इटावा-मैनपुरी नई लाइन (58 कि.मी.)	313
4	गाजीपुर सिटी-तारिघाट नई लाइन (17 कि.मी.)	1766
5	कानपुर-बरेली आमान परिवर्तन (545 कि.मी.)	1790

6	बरेली-टनकपुर आमान परिवर्तन (102 कि.मी.)	313
7	गोंडा-बहराइच आमान परिवर्तन (60 कि.मी.)	318
8	पीलीभीत-शाहजहांपुर आमान परिवर्तन (83 कि.मी.)	589
9	इंदारा-दोहरीघाट आमान परिवर्तन (34 कि. मी.)	213
10	लखनऊ-पीलीभीत आमान परिवर्तन (263 कि.मी.)	1634
11	उतरेतिया-जाफराबाद दोहरीकरण (148 कि.मी.)	890
12	भदोही-जंघई दोहरीकरण (31 कि.मी.)	168
13	मेरठ-मुजफ्फरनगर दोहरीकरण (55 कि.मी.)	430
14	मुजफ्फरनगर-तापरी दोहरीकरण (52 कि.मी.)	525
15	मथुरा-पलवल चौथी लाइन (80 कि.मी.)	669
16	उतरेतिया-रायबरेली दोहरीकरण (66 कि.मी.)	662
17	रायबरेली-अमेठी दोहरीकरण (60 कि.मी.)	668
18	भीमसेन-झांसी दोहरीकरण (206 कि.मी.)	2620
19	बलिया-गाज़ीपुर सिटी दोहरीकरण (65 कि.मी.)	650
20	औड़िहार-जौनपुर दोहरीकरण (60 कि.मी.)	405
21	बाराबंकी-अकबरपुर दोहरीकरण (161 कि.मी.)	1700
22	रोज़ा-बुढ़वल दोहरीकरण (181 कि.मी.)	2094
23	जौनपुर-अकबरपुर दोहरीकरण (77 कि.मी.)	676
24	रमना-सिंगरौली दोहरीकरण (160 कि.मी.)	2436
25	जंघई-फाफामऊ दोहरीकरण (47 कि.मी.)	414
26	वाराणसी-इलाहाबाद दोहरीकरण (120 कि.मी.)	2018

पूर्वांचल और जौनपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुछ मुख्य परियोजनाएं, जो शुरू की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	सहजनवा-दोहरीघाट नई लाइन (81 कि.मी.)	1320
2	बहराइच और खलीलाबाद नई लाइन (240 कि.मी.)	4940
3	ऊंचाहार-अमेठी दोहरीकरण (66 कि.मी.)	1229
4	मुगलसराय-इलाहाबाद, तीसरी लाइन (150 कि.मी.)	2649
5	बिल्ली-चुनार दोहरीकरण (102 कि.मी.)	1424
6	छपरा-बलिया दोहरीकरण (65 कि.मी.)	937
7	वाराणसी-इलाहाबाद दोहरीकरण (120 कि.मी.)	2018
8	डोमिनगढ़-कुसम्ही- तीसरी लाइन (21 कि.मी.)	508
9	बुढ़वल गोंडा तीसरी लाइन (62 कि.मी.)	800
10	फेफना-इंदारा, मऊ-शाहगंज दोहरीकरण (150 कि.मी.)	1529
11	भटनी-औड़िहार दोहरीकरण (125 कि.मी.)	2529
12	गोरखपुर-वाल्मीकिनगर दोहरीकरण (96 कि.मी.)	1121
13	जंघई-अमेठी दोहरीकरण (87 कि.मी.)	719
14	जंघई- फाफामऊ दोहरीकरण (47 कि.मी.)	414

रेलगाड़ियां:

चूँकि रेल नेटवर्क राज्यों/अंचलों की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है, इसलिए इन सीमाओं के आर-पार नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार रेलगाड़ियां शुरू की जाती हैं। बहरहाल, यात्रियों के लिए संपर्कता प्रदान करने में/सुधार करने के अपने निरंतर प्रयास में, भारतीय रेल ने 2023-24 और 2025-26 (31.07.2025 तक) की अवधि के बीच, गाड़ियों को आरंभिक/गंतव्य

स्थान के आधार पर, निम्नलिखित 22 रेलगाड़ी सेवाएँ शुरू की हैं, जिनमें गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, मऊ आदि स्टेशनों पर सेवित की जाने वाली 14 वंदे भारत गाड़ी सेवाएँ शामिल हैं।

1. 26501/26502 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
2. 20175/20176 बनारस-आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस
3. 22499/22500 देवघर-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
4. 20887/20888 रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
5. 22425/22426 अयोध्या कैंट-आनंद विहार (टर्मिनल) वंदे भारत एक्सप्रेस
6. 22415/22416 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस
7. 22549/22550 गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस
8. 18629/18630 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस
9. 16367/16368 कन्याकुमारी-बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस
10. 15181/15182 मऊ-लोकमान्य तिलक (टर्मिनल) एक्सप्रेस
11. 12945/12946 वेरावल-बनारस एक्सप्रेस

इसके अलावा, 12527/12528 आजमगढ़-आनंद विहार (टर्मिनल) एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है।

स्टेशन पुनर्विकास:

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच मार्ग, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह का कार्य और प्लेटफॉर्म पर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट

स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी स्टेशन संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य स्टेशन भवन में सुधार, शहर के दोनों भागों के साथ स्टेशन का एकीकरण, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के 157 स्टेशनों सहित 1,337 स्टेशनों को विकसित किए जाने के लिए चिह्नित किया गया है। देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में 20 स्टेशनों) अयोध्या धाम, बलरामपुर, बरेली सिटी, बिजनोर, फतेहाबाद, गोला गोकर्णनाथ, गोमतीनगर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, मैलानी, पुखरायां, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जं., सिद्धार्थ नगर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, उझानी) के चरण 1- के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है और उपरोक्त कुछ स्टेशनों पर कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:

- शाहगंज जंक्शन स्टेशन पर, 6 मीटर पैदल पार पुल और परिचलन क्षेत्र में चाहरदीवारी के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।
- जौनपुर जंक्शन स्टेशन पर, नए स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म शेल्टर और शौचालय ब्लॉक का संरचनात्मक कार्य शुरू किया गया है।
- जौनपुर सिटी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म शेल्टरों के कार्य शुरू किए गए हैं।

- मड़ियाहूँ स्टेशन पर, स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र, शौचालय, प्रतीक्षालय, प्रकाश व्यवस्था और दिव्यांगजन संबंधी सुविधाओं के कार्य शुरू किए गए हैं।
- बादशाहपुर स्टेशन पर, स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म शेल्टर, परिचलन क्षेत्र, शौचालय, प्रतीक्षालय, प्रकाश व्यवस्था और दिव्यांगजन संबंधी सुविधाओं के कार्य शुरू किए गए हैं।
- श्री कृष्ण नगर स्टेशन पर, स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म शेल्टर, परिचलन क्षेत्र, शौचालय, प्रतीक्षालय, लाइट की व्यवस्था और दिव्यांगजन सुविधाओं का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के कार्य सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करने, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्रियों की आवाजाही संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ व उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार अथवा स्टेशन-वार अथवा राज्य-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पाँच रेलवे ज़ोनों, अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, के क्षेत्राधिकार में आता है। इन ज़ोनों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 हेतु 4,357 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (जून, 2025 तक) 877 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों सहित रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, अतिलंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****